ISSN : 2347-7660 (Print) | ISSN : 2454-1818 (Online)

# वैश्वीकरण की चुनौतियाँ और भारतीय उच्च शिक्षा

**डॉ0 वीरेन्द्र सिंह यादव**

*एसोसिएट प्रोफेसर–हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग,*
*डॉ. शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,लखनऊ (उ.प्र.)*

शिक्षा मानव जीवन के विकास का मेरूदण्ड होने के साथ ही किसी भी राष्ट्र के उत्तरोत्तर विकास के लिए एक उत्कृष्ट साधन होती है। नियंत्रित शिक्षा की शुरूआत कहाँ एवं कब से हुई इसका कोई निश्चित प्रमाण नहीं प्राप्त होता है लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि मानव की बुद्धि साथ ही उसकी अनुमान करने की कालावधि के प्रत्येक छोर पर शिक्षा का अस्तित्व स्पष्ट दिखता है। अतीत की ओर जब हम देखतें है तो ''ऐतिहासिक काल से बहुत पहले मानव जब धीरे–धीरे जंगली जीवन छोड़कर सामाजिक जीवन की ओर बढ़ रहा था, सीखने का कार्य निश्चय ही अधिक अंश में अनुभव और अनुकरण पर आश्रित था, किन्तु प्रस्तर युग में भी किसी न किसी प्रकार की व्यवस्थित शिक्षा थी, इसका आभास भारत तथा यूरोप में उस काल से सम्बन्धित पशुओं के उन सुन्दर चित्रों से मिलता है, जो सिंहों पर, हाथी दाँत पर या गुफा की दीवारों पर खुदे हुए पाये गये हैं। मनुष्य का प्रत्येक कार्य किसी उद्देश्य से प्रेरित होता है।''(1)

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मुख्यतः पाशविक वृत्तियों का विनाश एवं मानव में मानवोचित सद्गुणों का विकास करना है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो आज अभिभावक, छात्र, समाज एवं स्वयं सरकार भी दिग्भ्रमित है। शिक्षा के निजीकरण, स्वायत्ता, कमरतोड़ बढ़ती फीस, शिक्षा का राजनीतिकरण साथ ही व्यापारीकरण के कारण गरीब एवं अमीरों के बीच की खाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है। शिक्षा के इस बढ़ते भव्य बाजार के कारण सामाजिक मूल्यों में गिरावट आ रही है। एक सामान्य व्यक्ति इसकी चकाचौंध एवं ग्लैमर देखकर हताशा कुंठा एवं आत्मगिलानि में डूबकर हताश–निराश की स्थिति में पहुँच गया है जहाँ गेट्स, अम्बानी, बिरला सलाह की समझौते के तहत शिक्षा को पानी, बिजली, कोकाकोला की तरह सर्विस सेक्टर में रखने की बात की जा रही है। वहीं वर्तमान के बदलते परिवेश में शिक्षा के ये पवित्र मन्दिर भव्य शोरूम की तरह हो गये हैं ऐसी स्थिति एवं परिस्थितियों में छात्र एक ग्राहक की तरह अपने प्राध्यापक से सेल्समैन की तरह बात करते हैं। भूमण्डलीकरण में बाजार एवं पैसा महत्वपूर्ण होता है इन स्थितियों में शिक्षा भी अब एजूकेशन बन गयी है। जिसका सम्बन्ध बाजार–व्यापार एवं वेतन–भोग एवं वेतनमान से है, न कि भारत, भारतीयता, संस्कृति एवं चरित्र से।''(2)

जब हम बात उच्च शिक्षा की ओर करें तो उच्च का शाब्दिक अर्थ है ऊँची, श्रेष्ठ अर्थात उच्च शिक्षा का सामान्य अर्थ हुआ, ''ऊँची शिक्षा, श्रेष्ठ शिक्षा ऐसी शिक्षा जो सामान्य शिक्षा से ऊँचे स्तर की हो। अंग्रेजी में इसे हायर एजूकेशन कहते हैं जिसका अर्थ है, उससे ऊँची शिक्षा अर्थात् सामान्य शिक्षा से ऊँची शिक्षा।''(3) स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा का वास्तविक अर्थ ऐसी शिक्षा से है जिसमें उच्च प्रतिभा के व्यक्तियों की उच्च शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा से है जिसके द्वारा समाज अथवा राष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विषय विशेषज्ञ तैयार किये जाते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

21वीं सदी का समाज ज्ञान का समाज होगा। आज मानव जाति शिक्षा के लिये अपरिहार्य सम्पदा के रूप में अवलोकन कर रही है क्योंकि शिक्षा, व्यक्तिगत एवं सामाजिक विकास की मूलभूत भूमिका में सामने आ रही है किसी भी व्यक्ति, समाज अथवा राष्ट्र की शक्ति का निर्धारण उसके ज्ञान की पूंजी के आधार पर निर्धारित होगा। आने वाले आगे के युद्ध तोप, टैंक या मिसाइल से नहीं, बल्कि सूचना और ज्ञान की ताकत से बाजार में लड़े जायेंगे – जो समाज अपने इतिहास से नहीं सीखता निश्चित तौर पर उसे निर्दित होना पड़ता है। जहाँ ''थाईलैण्ड, इंडोनेशिया, कोरिया जैसे छोटे–छोटे और कल के पिछड़े देश आज विकसित राष्ट्रों के साथ प्रतियोगिता कर आगे बढ़ने की चेष्टा कर रहे हैं।''(4) वहीं भारत अपनी पूरी आबादी की उच्च शिक्षा की बात छोड़ भी दे तो भी वह बुनियादी शिक्षा तथा स्वास्थ्य की सुविधायें उपलब्ध कराने में असफल रहा है। आज भी हमारे यहाँ आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी निरक्षरता की स्थिति से गुजर रहा है। भारत में ''आज की शिक्षा न तो अच्छा मानव बना पा रही है और न ही चुनौतियों से लड़ने की शक्ति दे पा रही है। पाठ्यक्रम भी बढ़ गये हैं, विद्यार्थी भी निरंतर बढ़ रहे हैं। परन्तु हम साक्षर जीवन के प्रति जागरूक नहीं हो पाये हैं शिक्षा के महत्व को नहीं समझ पा रहे हैं।''(5)

वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण के रक्त पिपासु पंजों व अधिकाधिक मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति ने उच्च शिक्षा को कमाऊ माल बनाकर निजी हाथों में सौंप दिया है जिससे बाजारोन्मुखी, प्रतिस्पर्धात्मक व उन्मुक्त अर्थपद्धति के आधार पर सम्पूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ही धारा में प्रवाहित करने का प्रयास दिनों–दिन तेज हो रहा है।''(6) उच्च शिक्षा में आ रही गिरावट को लेकर अब कहीं कोई मत भिन्नता नहीं रह गयी है। उच्च शिक्षा की वर्तमान पतनोन्मुख स्थिति को देखते हुये आने वाले भविष्य के प्रति मन आशंकित सा हमारी कल्पना को झकझोरने लगता है कि आखिर उच्च शिक्षा की इन स्थितियों एवं परिस्थितियों के पीछे कौन से ऐसे अवरोधक तत्व हैं जो इसे आगे बढ़ने में रोक रहे हैं साथ ही इन अवरोधक तत्वों से छुटकारा या अपेक्षित सुधार कैसे किया जाये जिससे भारतीय उच्च शिक्षा विकासशील देशों की श्रेणी से निकलकर विकसित देशों की श्रेणी में आ जाये। इस समय हमारे देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो मुख्य अवरोधक तत्व हैं उनके समाधान के लिये भी निरन्तर प्रयास जारी हैं, परन्तु वोट की राजनीति और ईमानदारी एवं कर्तव्यनिष्ठा की कमी के कारण इन समस्याओं का हल नहीं हो पा रहा है। यहाँ इन समस्याओं के स्वरूप, कारण एवं अवरोधक तत्व क्या हैं तथा गुणवत्ता के उच्च शिक्षा में क्या मानक हो सकते है ? कुछ शिक्षा में अवरोधक तत्व के कुछ प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं –

1. भारत में केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा नीतिगत प्रबन्धन में कमी।
2. शिक्षा मंत्रियों, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ–साथ महाविद्यालयों में प्राचार्यों की नेतृत्व क्षमता, कल्पना शक्ति एवं उच्च नैतिक शिक्षा के साथ आदर्शों में गिरावट।
3. कुछ संस्थाओं को छोड़ दे तो महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में अच्छे स्तर का शैक्षिक वातावरण एवं प्राकृतिक पर्यावरण का अभाव।
4. प्राध्यापक एवं छात्रों के अनुपात में मानकों के आधार एवं संख्या का अभाव।
5. छात्रों के लिये बनाई गई आचरण संहिता का अनुपालन न होने के कारण छात्रों के नैतिक आदर्शों में गिरावट।
6. राजनेताओं की छात्र राजनीति में अकारण, स्वार्थपरक सक्रिय दखलंदाजी।

7. महाविद्यालयों में प्रबन्धकारिणी समिति एवं कार्य परिषद के सम्मानित एवं बौद्धिक सदस्यों की कार्य करने में सक्रिय योगदान में कमी।

8. परिसर में स्वाध्याय कक्षों एवं उनमें अच्छी पुस्तकों के अभाव के साथ प्रयोगशाला सामग्री, शिक्षण हेतु आवश्यक उपकरणों का अभाव।

9. परिसरों में विज्ञान शिक्षा, कला विषयक शिक्षा, विधि शिक्षा आदि की अलग–अलग व्यवस्था से छात्रों में एक ही विषय का ज्ञान हो पाता है।

10. अध्यापन, अध्ययन, स्वाध्याय और सतत परीक्षा प्रबन्धन में कमी।

11. विषयों की पाठ्य सामग्री का रूचि पूर्ण एवं जीवन–उपयोगी न होना तथा छात्रों द्वारा कम परिश्रम से अधिक अंक प्राप्त करने की प्रवृत्ति।

12. संरक्षकों की अज्ञानता एवं उदासीनता भी उच्च शिक्षा के विकास में अवरोध का कार्य कर रहे हैं।

उच्च शिक्षा के गुणवत्ता स्तर में आयी इस कमी तथा इसके उत्तरोत्तर विकास में क्या परिवर्तन अपेक्षित हो सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि यू. जी. सी. जैसी स्वायत्तशासी संस्थाओं के माध्यम से एक ऐसा आयोग गठित हो जो केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित कर उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार करे तथा विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों को प्रोत्साहित कर उच्च शिक्षा की गुणवत्ता के उन्नयन में अग्रणी भूमिका निभा सके। वर्तमान में उच्च शिक्षा में जो परिवर्तन अपेक्षित हो सकते हैं उनमें प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं –

1. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी कार्य करने वाले एवं अनुभव रखने वाले प्रशासकों को मंत्री पद/कुलपति/प्राचार्य का दायित्व सौंपा जाये तथा उच्च शिक्षा सिद्धान्तों में शिक्षकों की बुनियादी अर्हता पी–एच.डी. के स्थान पर नेट/सेट/स्लेट भी अनिवार्य हो।

2. शैक्षिक सत्र नियमित होने के साथ–साथ ‘‘यू. जी. सी.’’(7) के नियमों का कड़ाई व ईमानदारी से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये जिससे एक सत्र में कम से कम 180 दिन कक्षायें चले व 75ः उपस्थिति पूरी न होने की स्थिति में छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति न दी जाये।

3. छात्रों की प्रवेश परीक्षा ली जाये उनसे उच्च शिक्षा में आने के कारण तथा इसके उद्देश्यों के बारे में जानकारी की जाये इसके साथ ही साथ प्राध्यापकों के मानकों के मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाये। फीड, बैक (प्रति पुष्टि) को अनिवार्य किया जाना तय हो।

4. वर्तमान परीक्षा प्रणाली तथा पाठ्यक्रमों में दैनिक जीवन से सम्बन्धित तथा वैज्ञानिक तथ्यों एवं सत्यों के आधार पर निर्धारण हो जिसको मापा एवं मूल्यांकित किया जा सके तथा वार्षिक परीक्षा प्रणाली के स्थान पर सेमेस्टर पद्धति का अनुपालन किया जाये।

5. महाविद्यालयों एवं निजी विश्वविद्यालयों को मान्यता देते समय सरकार उनके पूरे मानकों के पूर्ण होने पर ही उसे मान्यता प्रदान करें।

6. प्राध्यापक एवं कर्मचारियों को न्यूनतम तकनीकी (डिजिटल) एवं पुस्तकालयों में इण्टरनेट से जोड़ने की व्यवस्था सुनिश्चित हो।

7. विश्वविद्यालयों, तकनीकी संस्थानों तथा महाविद्यालयों में सीधे भर्ती न होकर संघ

लोक आयोग/लोक सेवा आयोग जैसी संस्थाओं के माध्यम से सुनिश्चित की जाये तथा अन्तर्राज्यीय स्तर पर महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाये।

8. शोध का वर्तमान स्वरूप (विज्ञान/कला) बदला जाये तथा उसके स्थान पर वैज्ञानिक सत्य एवं मानव जीवन के लिये अनुपयोगी ज्ञान पर आधारित मौलिक ज्ञान को वरीयता दी जाये।

9. उच्च शिक्षा में असहाय आर्थिक रूप से कमजोर दलित, पिछड़े किन्तु प्रतिभाशाली छात्र/छात्रा को ही अध्ययन एवं शोध हेतु वृत्ति मिलनी चाहिये।

10. छात्र संघ चुनाव छात्र हित में नहीं होने चाहिये यदि ऐसा आवश्यक हो तो उच्च शिक्षा में अपनी कक्षा में ताप करने वाले छात्र/छात्रा (अधिकतम अंक) को अध्यक्ष तथा उसके नीचे अंक पाने वाले छात्र/छात्रा को महामंत्री तथा इसी क्रम में अंक पाने वाले छात्र/छात्रा को पदों का दायित्व सौंपा जाये जिससे शैक्षिक माहौल का उत्तम विकास किया जा सकता है।

11. सरकारो को चाहिये कि उच्च शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के लिये प्रतिवर्ष शिक्षा के बजट में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाये।

स्पष्ट है कि किसी भी देश के पुनः निर्माण में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है इसमें सरकार की हिस्सेदारी/जिम्मेदारी के साथ–साथ देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि वह भी शैक्षिक जिम्मेदारियों का ईमानदारीपूर्वक निर्वहन करे क्योंकि शिक्षा एक ऐसी कारक होती है जो राष्ट्र की भावना एवं आवश्यकता के अनुरूप नागरिकों का निर्माण करती है। मानव संसाधन(8) के रूप में शिक्षा का महत्व निर्विवाद है। यहाँ इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि जिस तरह की शिक्षा–नीति पर हम, हमारा राष्ट्र कार्य करेगा, हमारा समाज उसी तरह का निर्मित होगा। भारत की सामाजिक, राजनैतिक परिस्थितियाँ शिक्षा को प्रभावित तो करती ही हैं साथ ही आर्थिक संसाधनों का अभाव भी शिक्षा पर अपना विशेष प्रभाव छोड़ता है। परिवर्तन के इस दौर में आज इस बात की विशेष आवश्यकता हो गई है कि हमें शिक्षा के विविध मानकों पर बहुत नजदीक से नजर रखनी होगी ताकि स्वस्थ्य राष्ट्र के स्वरूप का नवनिर्माण सुनिश्चित किया जा सके, इसमें कोई शक नहीं कि किसी भी राष्ट्र की उच्च शिक्षा में जितनी अधिक गुणवत्ता होगी, उस राष्ट्र का परिवेश उतना ही सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से सुदृढ़ तथा प्रबल होगा। इसलिये आज आवश्यक हो गया है कि उच्च शिक्षा के प्रतिमानों को पुनः परिभाषित करने के साथ–साथ शैक्षणिक वातावरण को पुनः स्थापित करने की महती आवश्यकता हो गयी है।

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूची


- भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, डॉ. रामशकल पाण्डेय, पृ. 5
- उच्च शिक्षा में अवरोधक तत्व स्मारिका, उरई 20, 21 मार्च 2005, पृ. 28
- भारतीय शिक्षा का विकास एवं उसकी समस्याएं, रमन बिहारी लाल, पृ. 416
- भारत की सामाजिक समस्याएं, एस. एन. ओझा, पृ. 259
- समकालीन अभिव्यक्ति, वाक्य बोध बदल गया है, प्रो. वाचस्पति उपाध्याय, पृ. 24

ISSN : 2347-7660 (Print) | ISSN : 2454-1818 (Online)


- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में अवरोधक तत्व, सेमिनार स्मारिका, 20, 21 मार्च 2006, पृ. 79
- सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल, भारत में शिक्षा का विकास, अरूण कुमार सहयोगी, पृ. 35
- सेमिनार स्मारिका, उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में अवरोधक तत्व, पृ. 49


*Copyright © 2014, Dr. Virendra Singh Yadav. This is an open access refereed article distributed under the creative common attribution license which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.*